अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 87 | श्री विजय पुरम, मंगलवार, 31 मार्च 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रुपए

कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा सेल्यूलर जेल में 'वंदे मातरम्' के सामूहिक गायन और 'शहीदी दिवस' का आयोजन

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी आयोजन के तहत कला एवं संस्कृति विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा गत 25 मार्च, 2026 को राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल में 'वंदे मातरम्' के सामूहिक गायन का कार्यक्रम आयोजित किया गया।

भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में 7 नवंबर, 2025 से 7 नवंबर, 2026 तक देशभर में मनाए जा रहे इस 150 वर्षीय समारोह के अंतर्गत 23 से 30 मार्च, 2026 तक 'शहीदी दिवस' को समर्पित विशेष चरण आयोजित किया गया। इस दौरान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

इस अवसर पर 'सुर सप्तक' के सदस्यों ने 'वंदे मातरम्' का भावपूर्ण सामूहिक गायन प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में पर्यटकों एवं आगंतुकों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली, जिसने गर्व और देशभक्ति की सामूहिक भावना को दर्शाया। पूरा वातावरण राष्ट्रीय गीत के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व के प्रति एकता और श्रद्धा से ओतप्रोत रहा।

कला एवं संस्कृति निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम के दौरान हमारे राष्ट्रीय नायकों भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के सर्वोच्च बलिदानों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम का समापन सामूहिक गौरव के भाव के साथ हुआ, जिसमें सभी प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय गीत में निहित आदर्शों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराया।

माननीय उप राज्यपाल की पूज्य माता जी श्रीमती हंसा जोशी के निधन पर संवेदना व्यक्त

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

समाज के विभिन्न वर्गों एवं संगठनों ने अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल एवं द्वीप विकास एजेंसी के उपाध्यक्ष, एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.) की पूज्य माता जी श्रीमती हंसा जोशी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। उनका गत 28 मार्च को श्री विजय पुरम के जी बी पंत अस्पताल में 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया।

प्राप्त प्रेस विज्ञप्तियों में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद श्री बिष्णु पद राय ने श्रीमती हंसा जोशी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया। अपने शोक संदेश में उन्होंने कहा कि माँ का निधन अपार एवं अपूरणीय क्षति है, और इस दुख की गहराई को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि माँ का प्रेम, स्नेह और आशीर्वाद अतुलनीय होता है और उनके जाने से जो खालीपन आता है, उसे कभी भरा नहीं जा सकता। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की तथा शोक संतप्त परिवार को इस कठिन समय में धैर्य, साहस एवं संबल प्रदान करने की कामना की। साथ ही उन्होंने उप राज्यपाल एडमिरल डी. के. जोशी एवं उनके परिवार के प्रति अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

भारतीय जनता पार्टी, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के प्रदेश अध्यक्ष श्री अनिल कुमार तिवारी ने भी अपनी ओर से तथा पार्टी के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की ओर से गहरी संवेदना व्यक्त की। अण्डमान निकोबार चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष डॉ. के. चंद्रशेखर एवं सभी सदस्यों ने भी गहरा शोक व्यक्त किया। अण्डमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स (एएटीओ) के अध्यक्ष श्री एम. विनोद एवं सभी सदस्यों ने भी दिवंगत आत्मा के प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित की।

'अनिम्स' में स्वास्थ्य कर्मियों हेतु चिकित्सा–विधि जागरूकता सत्र संचालित

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह द्वारा ज़िला न्यायपालिका एवं 'प्रयास' जेएसी सोसाइटी, श्री विजय पुरम के सहयोग से आज अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह स्वास्थ्य संस्थान (अनिम्स) के लेक्चर हॉल में स्वास्थ्य पेशेवरों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य–विधि । जागरूकता सत्र का आयोजन किया गया। यह सत्र हाइब्रिड मोड में आयोजित किया गया, जिससे प्रतिभागियों को भौतिक एवं ऑनलाइन दोनों माध्यमों से भाग लेने की सुविधा मिली। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा निदेशालय एवं 'अनिम्स' के डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को चिकित्सा अभ्यास से संबंधित कानूनी प्रावधानों, नैतिक ज़िम्मेदारियों एवं अधिकारों के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना था।

कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन ज़िला विधि सेवा प्राधिकरण एवं ज़िला न्यायपालिका के गणमान्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. एच.एम. सिद्धाराजू एवं 'अनिम्स' के प्रभारी निदेशक डॉ. एम. के. साहा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 'प्रयास' जेएसी सोसाइटी की क्षेत्रीय प्रमुख श्रीमती मरिया शीला, सलाहकार श्री के. विजय कुमार तथा 'प्रयास' के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस सत्र में न्यायिक अधिकारियों ने संसाधन व्यक्तियों के रूप में भाग लेकर महत्वपूर्ण चिकित्सा–विधि एवं सामाजिक विषयों पर जानकारीपूर्ण व्याख्यान दिए। प्रमुख वक्ताओं में श्री राशिद आलम (रजिस्ट्रार, कलकत्ता उच्च न्यायालय, सर्किट बेंच, पोर्ट ब्लेयर एवं सदस्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार राज्य विधि सेवा प्राधिकरण), श्री नेयाज़ आलम (अपर ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश, पोर्ट ब्लेयर), श्री दीपेंद्र नाथ मित्रा (न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, पोर्ट ब्लेयर), श्री सम्राट रॉय (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट–सह–सचिव,

शेष पृष्ठ 4 पर

स्वराज द्वीप में लंबित भूमि डायवर्जन मामलों के निस्तारण हेतु दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने लगाया शिविर अदालत

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

दक्षिण अण्डमान ज़िला प्रशासन ने श्री विजय पुरम तहसील के अंतर्गत स्वराज द्वीप से संबंधित लंबे समय से लंबित भूमि डायवर्जन मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक विशेष पहल की है, जिसका उद्देश्य सेवा वितरण में सुधार करना और लंबित मामलों को कम करना है।

इसी क्रम में 28 मार्च, 2026 को स्वराज द्वीप के गोविंद नगर स्थित पंचायत भवन में शिविर अदालत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सहायक आयुक्त, दक्षिण अण्डमान, श्री कमलेश्वर राव एस. (आईएएस) ने की। शिविर अदालत का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र स्तर पर लंबित भूमि डायवर्जन मामलों का समाधान कर आवेदकों को समयबद्ध एवं सुलभ न्याय प्रदान करना था।

कार्यवाही के दौरान 118 मामलों में नोटिस जारी किए गए, जिनमें से 89 मामलों में सुनवाई की गई। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2009 से लंबित कई पुराने मामलों को भी विचारार्थ लिया गया। मौके पर ही समाधान सुनिश्चित करने हेतु भूमि डायवर्जन प्रीमियम जमा करने की व्यवस्था की गई, जिससे आवेदक आवासीय एवं व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूर्ण कर सकें।

इस पहल से निर्णय प्रक्रिया में तेजी आई तथा लंबित मामलों में उल्लेखनीय कमी दर्ज़ की गई, जिससे आवेदकों को काफी राहत मिली। भूमि डायवर्जन के अलावा स्थानीय निवासियों द्वारा उठाई गई विभिन्न जन शिकायतों का भी निवारण शिविर अदालत के दौरान किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह पहल प्रशासन की विशेष रूप से दूरस्थ एवं द्वीपीय क्षेत्रों में सुशासन, पारदर्शिता एवं त्वरित शिकायत निवारण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ज़िला प्रशासन भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम आयोजित करता रहेगा, जिससे सरकारी सेवाओं की पहुंच बढ़े और लंबित मामलों में और कमी लाई जा सके।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने हेतु जिप अध्यक्ष ने किया कई परियोजनाओं का उद्घाटन

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

दक्षिण अण्डमान ज़िला परिषद के अध्यक्ष श्री प्रकाश अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जनसुविधाओं को मजबूत करने और कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से कई सामुदायिक अवसंरचना परियोजनाओं का कल उद्घाटन किया गया। वंडूर–02 में नवनिर्मित रसोई शेड एवं स्टोर रूम सहित नवीनीकृत सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया गया। यह उन्नत सुविधा सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सामुदायिक गतिविधियों के आयोजन के लिए स्थानीय निवासियों को बेहतर और सुसज्जित स्थान प्रदान करेगी। इस अवसर पर श्री भरत शर्मा (पंचायत समिति सदस्य, वंडूर), श्री अधीर दास (प्रधान, वंडूर पंचायत), श्री उत्तम कुमार रॉय (उप–प्रधान, वंडूर पंचायत),

शेष पृष्ठ 4 पर

ज़िला अस्पताल, गाराचरामा में इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब का उद्घाटन

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

ज़िला अस्पताल, गाराचरामा, श्री विजय पुरम में आज इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैबोरेटरी (आईपीएचएल) का औपचारिक उद्घाटन वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों और विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर सचिव (स्वास्थ्य)/मिशन निदेशक, यूटीएचएम, श्रीमती वंदना राव (आईएएस) मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहीं, जबकि स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ. एच. एम. सिद्धाराजू विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए।

आईपीएचएल की स्थापना अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के उस मिशन में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिसका उद्देश्य उन्नत और विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है। इस प्रयोगशाला के माध्यम से संक्रामक रोगों की जांच, हीमेटोलॉजी, क्लीनिकल बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी जैसी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी, जिससे मरीज़ों को बेहतर और सुगम उपचार मिल सकेगा।

उद्घाटन समारोह के बाद, श्रीमती वंदना राव ने नवस्थापित आईपीएचएल सुविधा का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न प्रयोगशालाएं और टीकाकरण कक्ष शामिल हैं। इस दौरान डॉ. अविजीत रॉय, एनओ, पीएम–एबीएचआईएम, स्वास्थ्य सेवा निदेशालयस तथा जीबी पंत अस्पताल, श्री विजय पुरम की माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉ. शाहिना एम. ने प्रयोगशाला में किए जाने वाले विभिन्न चिकित्सा परीक्षणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी और क्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन

शेष पृष्ठ 4 पर

शहरी क्षेत्रों के जनगणना कर्मियों हेतु प्रशिक्षण जारी

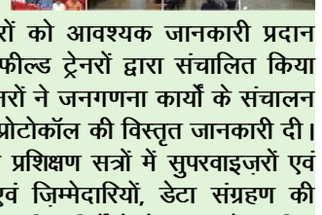

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

शहरी क्षेत्रों के जनगणना कर्मियों के लिए आज चार विभिन्न स्थानों–एसवीपीएमसी ऑडिटोरियम, गर्ल्स स्कूल ऑडिटोरियम, आईसीसीसी भवन (लिंक रोड) एवं डीब्राइट कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण निर्धारित सुपरवाइज़रों एवं गणनाकारों को आवश्यक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से नियुक्त फील्ड ट्रेनरों द्वारा संचालित किया गया। कार्यक्रम के दौरान ट्रेनरों ने जनगणना कार्यों के संचालन हेतु आवश्यक प्रक्रियाओं एवं प्रोटोकॉल की विस्तृत जानकारी दी।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रशिक्षण सत्रों में सुपरवाइज़रों एवं गणनाकारों की भूमिकाओं एवं ज़िम्मेदारियों, डेटा संग्रहण की विधियों तथा निर्धारित जनगणना दिशानिर्देशों के पालन से संबंधित

शेष पृष्ठ 4 पर

'अनिडको' के आईएमएफएल एवं पेट्रोलियम इकाइयाँ 31 मार्च को बंद रहेंगी

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

आम जनता को सूचित किया गया है कि अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह एकीकृत विकास निगम लिमिटड (अनिडको) की सभी आईएमएफएल एवं पेट्रोलियम इकाइयों के वार्षिक भौतिक सत्यापन (फिज़िकल वेरिफिकेशन) के कारण दिनांक 31 मार्च, 2026 को निम्नलिखित इकाइयाँ बंद रहेंगी:

क्र.सं.	इकाइयां	समय
1.	सभी आईएमएफएल इकाइयाँ	दोपहर 1 बजे से आगे
2.	पीओएल, जंगलीघाट	रात्रि 9 बजे से तड़के 12 बजे तक
3.	अन्य सभी पेट्रोलियम इकाइयां	दोपहर 2 बजे से आगे

सागरिका एम्पोरियम के आउटलेट 4 से 6 अप्रैल तक रहेंगे बंद

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

उद्योग निदेशालय से प्राप्त विज्ञप्ति में आम जनता को सूचित किया गया है कि उद्योग निदेशालय के अंतर्गत संचालित अण्डमान तथा निकोबार एम्पोरियम–सागरिका के मिडिल पॉइंट, वीएसआई एयरपोर्ट, सेल्यूलर जेल तथा राधानगर स्थित सभी आउटलेट वार्षिक स्टॉक सत्यापन एवं सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण 4 से 6 अप्रैल तक बंद रहेंगे। इस अवधि के दौरान उपरोक्त सभी आउटलेट्स में व्यापार/संचालन पूर्णतः स्थगित रहेगा।

लिटिल अण्डमान में लकड़ी शिल्प प्रशिक्षण सम्पन्न

लिटिल अण्डमान, 30 मार्च

सामुदायिक खंड विकास, लिटिल अण्डमान द्वारा डीएवाई–एनआरएलएम के अंतर्गत उद्योग विभाग, हटबे के सहयोग से समिति सम्मेलन कक्ष में 30 दिवसीय लकड़ी हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन समारोह का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभागियों के कौशल विकास को बढ़ावा देना तथा स्वरोज़गार के अवसरों को प्रोत्साहित करना था। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित लिटिल अण्डमान के प्रमुख, श्री एस. परमनाथन ने प्रतिभागियों को ऐसे कौशल विकास कार्यक्रमों में निरंतर भाग लेने के लिए प्रेरित किया। लिटिल अण्डमान के तहसीलदार, श्री अजय मंडल भी कार्यक्रम में विशिष्ट

अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने 30 दिनों के प्रशिक्षण के दौरान तैयार किए गए विभिन्न लकड़ी के हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन किया, जो उनकी रचनात्मकता, कौशल और समर्पण को दर्शाते थे।

जंगलीघाट मत्स्य अवतरण केंद्र पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

मत्स्य विभाग ने श्री विजय पुरम नगरपालिका परिषद के सहयोग से जंगलीघाट स्थित फिश लैंडिंग सेंटर पर व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया, जिसका उद्देश्य जनस्वास्थ्य सुनिश्चित करना, मछलियों की गुणवत्ता बनाए रखना तथा सतत मात्स्यिकी को बढ़ावा देना था। यह स्वच्छता अभियान फरवरी, 2026 के दौरान तथा 26 से 28 मार्च तक दो चरणों में संचालित किया गया, जिसमें विभागीय अधिकारियों एवं मछुआरा समुदाय ने सक्रिय भागीदारी निभाई। अभियान के दौरान बड़ी मात्रा में कचरा हटाया गया, जिसमें घोस्ट नेट, उपयोग किए गए एवं टूटे हुए थर्माकोल तथा क्षतिग्रस्त नावों के हिस्से शामिल थे, जो लंबे समय से एकत्रित थे। इस व्यापक अभियान के अंतर्गत कुल 15 ट्रक कचरा हटाया गया, जो पर्यावरण प्रबंधन एवं स्थल की कार्यक्षमता में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल के तहत स्थानीय मछुआरों को उचित कचरा निपटान के महत्व के बारे में जागरूक भी किया गया तथा उन्हें समुद्र या आसपास के क्षेत्रों में कचरा न फेंकने के लिए प्रेरित किया गया। जागरूकता कार्यक्रमों में समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा एवं स्वच्छता बनाए रखने के महत्व पर विशेष ज़ोर दिया गया।

इग्नू ने 39वें दीक्षांत समारोह की तिथि घोषित की

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) का 39वां दीक्षांत समारोह आगामी 7 अप्रैल, 2026 को इग्नू मुख्यालय तथा क्षेत्रीय केंद्र, पोर्ट ब्लेयर में एक साथ आयोजित किया जाएगा। दिसंबर, 2024 एवं जून, 2025 की सत्रावधि परीक्षाओं में अपना अध्ययन कार्यक्रम पूर्ण करने वाले शिक्षार्थी इस दीक्षांत समारोह में प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री प्राप्त करने के पात्र होंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार क्षेत्रीय केंद्र पोर्ट ब्लेयर के ऐसे पात्र छात्र–छात्राएं, जिन्होंने 39वें दीक्षांत समारोह हेतु पंजीकरण प्रपत्र पहले ही जमा कर दिया है, उनसे अनुरोध है कि वे वीआईपी रोड के निकट स्थित क्षेत्रीय केंद्र कार्यालय से अपना स्कार्फ प्राप्त कर लें। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए शिक्षार्थी इग्नू क्षेत्रीय केंद्र, श्री विजय पुरम, पिन–744103 दूरभाष संख्या 03192–230111/242888 या ईमेल rcportblair@ignou.ac.in से संपर्क कर सकते हैं।

शहरी क्षेत्रों के जनगणना कर्मियों ——पृष्ठ 1 का शेष

महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य सभी कर्मियों को आगामी जनगणना कार्यों के प्रभावी एवं सुचारु संचालन के लिए आवश्यक ज्ञान एवं कौशल से सुसज्जित करना था। यह कार्यक्रम सभी स्थानों पर सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि जनगणना कर्मी शहरी क्षेत्रों में जनगणना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगामी दो दिनों तक जारी रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को ——पृष्ठ 1 का शेष

श्री मोहन बाला (वार्ड सदस्य, वंडूर–02), श्री निर्मल सरकार (पंचायत समिति सदस्य, गुप्तापाड़ा), श्री दुर्लभ दास (प्रधान, गुप्तापाड़ा पंचायत) तथा श्री एस. त्रिनादुलु (वार्ड सदस्य, मंगलूटान–2) भी उपस्थित रहे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इसके साथ ही, नॉर्थ वंडूर जंक्शन पर यात्रियों एवं स्थानीय निवासियों की सुविधा के लिए शौचालय सहित बस शेल्टर के निर्माण हेतु शिलान्यास भी किया गया। इसके अतिरिक्त, मंगलूटान–1 (गुप्तापाड़ा) में तपस बनिक के निवास तक, रवि बनिक के घर के रास्ते से मुख्य सड़क को जोड़ने वाली नई ब्लैक टॉप सड़क का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना स्थानीय लोगों के लिए आवागमन को सुगम बनाने और कनेक्टिविटी में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इन कार्यक्रमों में इंजीनियरिंग स्टाफ, पंचायत सदस्य, जनप्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

ज़िला अस्पताल, गाराचरामा में इंटीग्रेटेड ——पृष्ठ 1 का शेष

स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए बुनियादी ढांचे के विकास और प्रभावी सेवा वितरण के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी अंतर को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम–एबीएचआईएम) के तहत समर्थित यह पहल द्वीपों को भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए बेहतर रूप से तैयार करेगी।

'अनिम्स' में स्वास्थ्य कर्मियों हेतु ——पृष्ठ 1 का शेष

डीएलएसए) तथा श्री अनुपम सरकार (अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, पोर्ट ब्लेयर) शामिल थे। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार सत्र में डॉक्टरों, नर्सों एवं अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों ने ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से सक्रिय भागीदारी की, जिससे सार्थक चर्चा हुई और स्वास्थ्य क्षेत्र में कानूनी सुरक्षा एवं पेशेवर ज़िम्मेदारियों के प्रति जागरूकता बढ़ी। कार्यक्रम का समापन डॉ. एम. के. साहा द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। उन्होंने सभी वक्ताओं, 'अनिम्स', स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, 'प्रयास' जेएसी सोसाइटी एवं संबंधित सभी संस्थाओं के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया तथा प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी की सराहना की।

कालीकट स्कूल मैदान में ब्लॉक एसएचजी मेला का सफल आयोजन

श्री विजयपुरम, 30 मार्च

सामुदायिक विकास खंड, प्रोथरापुर, दक्षिण अण्डमान द्वारा आयोजित दो दिवसीय ब्लॉक एसएचजी मेला 2026 का आयोजन 28 एवं 29 मार्च, 2026 को कालीकट स्थित राजकीय प्रवर माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में सफलतापूर्वक किया गया। यह कार्यक्रम कालीकट एवं बिड़नाबाद ग्राम पंचायतों के सहयोग से आयोजित किया गया। मेले का उद्घाटन डॉ. अपूर्वा शर्मा, निदेशक (ग्रामीण विकास/पंचायती राज संस्थान) द्वारा किया गया। उन्होंने एसएचजी सदस्यों के प्रयासों की सराहना की। अपने दौरे के दौरान उन्होंने प्रतिभागियों से संवाद किया, सभी स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में उनके योगदान को प्रोत्साहित किया।

इस मेले में बिड़नाबाद, कालीकट, सीपीघाट और स्वराज द्वीप ग्राम पंचायतों के स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सदस्यों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। 40 से अधिक स्टॉल लगाए गए। मेले के दौरान प्रतिभागी समूहों ने लगभग 2,90,000 रुपये की कुल बिक्री दर्ज़ की। एसएचजी स्टॉलों के अतिरिक्त, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, एसबीआई–आरएसईटीआई और क्रिसिल सहित विभिन्न सरकारी विभागों ने भी अपने स्टॉल लगाकर योजनाओं एवं पहलों के प्रति जागरूकता फैलायी।

दोनों दिनों में बड़ी संख्या में लोगों ने मेले में भाग लिया, जिससे उत्सव जैसा वातावरण बना रहा। आम जनता के लिए कई रोचक खेलों का आयोजन किया गया तथा एसएचजी सदस्यों एवं स्थानीय बच्चों के नृत्य समूहों द्वारा प्रस्तुत रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने मेले की शोभा बढ़ाई।

समापन दिवस पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले स्टॉलों एवं विभिन्न खेलों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, गणमान्य व्यक्तियों एवं स्वयंसेवकों को भी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार प्रोथरापुर की बीडीओ श्रीमती गुरजीत कौर ने एसएचजी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी तथा ग्राम पंचायतों एवं स्वयंसेवकों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कालीकट पंचायत के प्रधान श्री टी. यघम्बरम एवं उनकी टीम के समन्वय और मेले के सफल संचालन, विशेषकर स्थल की स्वच्छता बनाए रखने के प्रयासों की सराहना की।

कॉलिनपुर तट पर चला स्वच्छता अभियान

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

आयुष स्कंध, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा 28 मार्च को दक्षिण अण्डमान के कॉलिनपुर तट पर कॉलिनपुर पंचायत के सहयोग से तट स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। इस अभियान में आयुष विभाग के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। सभी ने मिलकर सफाई कार्य, कचरा संग्रहण तथा तटीय पारिस्थितिकी तंत्र की स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने में योगदान दिया।

इस अभियान में प्रधान श्रीमती सुजाता सिंह, श्री बलराम सिंह (समाजसेवी) तथा पंचायत के अन्य सदस्यों और कर्मचारियों ने भी सक्रिय रूप से भाग लिया। उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए श्रीमती सुजाता सिंह ने पर्यावरण जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग के प्रयासों की सराहना की। वन विभाग के अधिकारियों द्वारा मगरमच्छों से सुरक्षा संबंधी जागरूकता सत्र भी आयोजित किया गया, जिसमें आम जनता के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी गई। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉ. किर्तिका चंदर, चिकित्सा अधिकारी (होम्योपैथी) द्वारा अन्य टीम सदस्यों के सहयोग से किया गया। यह पहल एक स्वस्थ और स्वच्छ समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान साबित हुई।

ओरलकच्छा स्कूल में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण संपन्न

मायाबंदर, 30 मार्च

अग्निशमन केंद्र बाराटांग, मध्य अण्डमान के अग्निशामकों द्वारा राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, ओरलकच्छा में अग्नि सुरक्षा निरीक्षण किया गया, ताकि स्कूल सुरक्षा मूल्यांकन उपकरण (एसएसएटी) के मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित किया जा सके। निरीक्षण के दौरान अग्निशामक यंत्रों की कार्यस्थिति की जांच की गई तथा शिक्षकों को अग्नि सुरक्षा एवं अग्निशामक यंत्रों के उपयोग के संबंध में व्यवहारिक

प्रशिक्षण प्रदान किया गया। आगे आवश्यक सुधार के लिए सुझाव भी विद्यालय प्रबंधन को दिए गए। उत्तर व मध्य अण्डमान के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस पहल का उद्देश्य अग्नि सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करना, आपातकालीन तैयारियों को बेहतर बनाना तथा कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना है।

मंगलूटान में आयोजित शिविर में 18 पशुओं की जांच

श्री विजय पुरम, 30 मार्च

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा पशु चिकित्सालय, मंगलूटान, दक्षिण अण्डमान के अधिकार क्षेत्र में कल एक व्यापक घर–घर जाकर अनुवर्ती बांझपन निवारण शिविर का सफल आयोजन किया गया। पशु चिकित्सा टीमों ने किसानों के घर–घर जाकर कुल 18 पशुओं की जांच की। इनमें से 6 पशु क्लीनिकल जांच के माध्यम से गर्भवती पाए गए, जिससे संबंधित पशुपालकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शेष 12 पशुओं को आवश्यक उपचार प्रदान किया गया तथा बांझपन से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु विस्तृत प्रबंधन संबंधी सलाह दी गई।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस शिविर से सीधे तौर पर 13 किसानों को लाभ मिला, जिन्हें उचित प्रजनन प्रबंधन, संतुलित पोषण, समय पर पशु चिकित्सा हस्तक्षेप, हीट पहचान तथा पशुओं की प्रजनन क्षमता और समग्र उत्पादकता बढ़ाने के लिए आवश्यक वैज्ञानिक पद्धतियों के बारे में जागरूक किया गया।

डिगलीपुर के रामनगर तट पर "चेकमेट प्लास्टिक" स्वच्छता एवं शतरंज कार्यक्रम हुआ

डिगलीपुर, 30 मार्च

"चेकमेट प्लास्टिक–शतरंज एवं स्वच्छता अभियान" का सफल आयोजन हाल ही में उत्तर अण्डमान के डिगलीपुर के रामनगर तट पर किया गया, जिसे हाल ही में पायलट ब्लू फ्लैग तट घोषित किया गया है, जो स्वच्छता, स्थिरता और पर्यावरण प्रबंधन के उच्च मानकों का प्रतीक है। इस कार्यक्रम का आयोजन अण्डमान निकोबार शतरंज एसोसिएशन (एएनसीए) द्वारा ग्राम पंचायत रामनगर एवं रेंज कार्यालय कालीघाट, डिगलीपुर प्रभाग के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन श्री शिवेन्द्र सिंह, सहायक वन संरक्षक, डिगलीपुर प्रभाग द्वारा शतरंज की बिसात पर पहली चाल चलकर किया गया। इस पहल में स्थानीय ग्रामीणों, पर्यटकों एवं शतरंज प्रेमियों ने बड़ी संख्या में उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत तट सफाई अभियान से हुई, जिसमें प्रतिभागियों ने प्लास्टिक एवं अन्य कचरे को एकत्र कर रामनगर तट की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने में योगदान दिया। इसके बाद सभी आयु वर्ग के खिलाड़ियों को शामिल करते

हुए शतरंज प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार समापन समारोह के दौरान, उत्कृष्ट शतरंज खिलाड़ियों एवं स्वच्छता अभियान में सक्रिय प्रतिभागियों को ग्राम पंचायत रामनगर के प्रधान श्री मिथुन दास एवं कालीघाट के रेंज अधिकारी श्री गोविंद राज द्वारा पुरस्कृत किया गया। यह कार्यक्रम "प्लास्टिक को मात देना और हमारे समुद्र तट की रक्षा करते हुए शतरंज को बढ़ावा देना" विषय पर आधारित था।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

ई–निविदा सूचना

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है भले हो उनकी सूची इस शर्ते पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/25–26/टीडी–29
कार्य का नामः सुभाषग्राम, डिगलीपुर में दुग्ध शीतलन केंद्र की मरम्मत और रख–रखाव।
अनुमानित लागत : रु. 4,57,157/–
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं
बयाना राशि : रु. 9,145/–
कार्य पूर्ण करने की अवधि : 30 दिन
निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि : 28/03/2026
निविदा दस्तावेज डाउनलोड/आरंभ तिथि : 30/03/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि : 08/04/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 15/04/2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि : 16/04/2026 के पूर्वाह्न 11.30 बजे
निविदा प्रपत्र और अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
निविदा आईडी 2026_ANCVL_22542_1

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

ई–निविदा सूचना

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है भले हो उनकी सूची इस शर्ते पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/25–26/टीडी–30
कार्य का नामः नवग्राम, डिगलीपुर में दुग्ध शीतलन केंद्र की मरम्मत और रख–रखाव।
अनुमानित लागत : रु. 2,86,931/–
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं
बयाना राशि : 5,740/–
कार्य पूर्ण करने की अवधि : 30 दिन
निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि : 28/03/2026
निविदा दस्तावेज डाउनलोड/आरंभ तिथि : 30/03/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि : 08/04/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 15/04/2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि : 16/04/2026 के पूर्वाह्न 11.00 बजे
निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
निविदा आईडी : 2026_ANCVL_22543_1

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

ई–निविदा सूचना

अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह समन्वित विकास निगम लिमिटेड, विकास भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 180, श्री विजय पुरम (अनिडको) की ओर से अलोनिवि या किसी अन्य सरकारी विभाग के ठेकेदारों से ऑनलाइन मद दर ई–निविदाएं आमंत्रित की जाती है भले हो उनकी सूची इस शर्ते पर हो कि उन्हें सीपीडब्ल्यूडी वर्कस मैनुअल के अनुसार और इन द्वीपों में अन्य भारत सरकार संगठनों के साथ कार्य के प्रासंगिक परिमाण को क्रियान्वित करने का अनुभव है और उनके पास कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है :

एन.आई.टी.सं. अनिडको/सीडब्लू/25–26/टीडी–31
कार्य का नामः टुगापुर, मायाबंदर में दुग्ध शीतलन केंद्र की मरम्मत और रख–रखाव।
अनुमानित लागत : रु. 4,28,172/–
निविदा/बोली प्रसंस्करण शुल्क : लागू नहीं
बयाना राशि : रु. 8,565/–
कार्य पूर्ण करने की अवधि : 30 दिन
निविदा दस्तावेज प्रकाशन तिथि : 28/03/2026
निविदा दस्तावेज डाउनलोड/आरंभ तिथि : 30/03/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की आरंभ तिथि : 08/04/2026 के पूर्वाह्न 10.00 बजे
निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि : 15/04/2026 के अपराह्न 3.00 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि : 16/04/2026 के पूर्वाह्न 11.45 बजे
निविदा प्रपत्र एवं अन्य विवरण वेबसाइट https://eprocure.andamannicobar.gov.in से प्राप्त किए जा सकते हैं।
निविदा आईडी : 2026_ANCVL_22544_1

महाप्रबंधक (सिविल कार्य), अनिडको

डब्ल्यूटीओ में भारत ने छोटे मछुआरों के हितों की वकालत की

याउंडे, 30 मार्च।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने विश्व व्यापार संगठन के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में मत्स्य सब्सिडी के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखते हुए कहा कि अत्यधिक क्षमता और अधिक मछली पकड़ने की समस्या भारी सब्सिडी प्राप्त औद्योगिक बेड़ों के कारण उत्पन्न होती है, न कि भारत और अन्य विकासशील देशों के छोटे मछुआरों से।

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार, कैमरून के याउंडे में 26 से 29 मार्च तक आयोजित इस सम्मेलन में मत्स्य सब्सिडी प्रमुख एजेंडा रहा। भारत ने चरण–2 वार्ताओं के लिए मंत्रीस्तरीय निर्णय को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाई और समानता तथा सतत विकास के सिद्धांतों पर जोर दिया।

भारत ने स्पष्ट किया कि विकासशील देशों और अल्पविकसित देशों के लिए विशेष एवं भिन्न उपचार, समान लेकिन अलग–अलग जिम्मेदारियों तथा प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को वार्ता का आधार बनाया जाना चाहिए। भारत ने 25 वर्ष की संक्रमण अवधि, छोटे और पारंपरिक मछुआरों के लिए स्थायी छूट, तथा औद्योगिक दूरस्थ जल बेड़ों पर कड़े नियमों की वकालत की।

श्री गोयल ने कहा कि भारत का मत्स्य क्षेत्र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और आजीविका प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देश में 90 लाख से अधिक मछुआरा परिवार इस क्षेत्र पर निर्भर हैं, जिनमें अधिकांश छोटे, पारंपरिक और कारीगर मछुआरे हैं, जो टिकाऊ तरीकों से मछली पकड़ते हैं।

उन्होंने कहा कि भारत न तो भारी औद्योगिक मत्स्य राष्ट्र है और न ही यहां बड़े पैमाने पर दूरस्थ जल में मछली पकड़ने वाले बेड़े हैं। भारत में प्रति मछुआरा परिवार सब्सिडी भी वैश्विक स्तर पर बहुत कम है, जो लगभग 15 अमेरिकी डॉलर सालाना है, जबकि कई देशों में यह हजारों डॉलर तक पहुंचती है। केंद्रीय मंत्री ने भारत के संतुलित और जन–केंद्रित दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुए कहा कि देश ने लंबे समय से संरक्षण के उपाय अपनाए हैं, जैसे वार्षिक मछली पकड़ने पर प्रतिबंध, जो सतत विकास के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारत ने डब्ल्यूटीओ मंच पर यह भी जोर दिया कि भविष्य के निर्णय न्यायसंगत और संतुलित होने चाहिए, ताकि कमजोर और छोटे मछुआरा समुदायों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

शपथ पत्र

मैं एस. निथिन, पिता श्री के. नारायणन कुट्टी, आयु लगभग 23 वर्ष, निवासी अनीझम इंजीनियरिंग वर्क्स, जीरो प्वाइंट, कैम्पबेल बे, ग्रेट निकोबार, निकोबार जिला, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह–744302, शपथपूर्वक निम्नलिखित कथन करता हूँ :

1. कि मैं इस शपथ पत्र का अभिकर्ता हूँ तथा इसे प्रस्तुत करने हेतु पूर्णतः सक्षम हूँ।
2. कि मेरे पिता का नाम 'के. नारायणन कुट्टी' मेरे आधिकारिक पहचान दस्तावेजों, जैसे आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस में सही रूप से अंकित है।
3. कि मेरे विद्यालय एवं शैक्षिक अभिलेखों में मेरे पिता का नाम त्रुटिवश 'नारायणन कुट्टी' अंकित हो गया है जो कि एक लिपिकीय/टंकण त्रुटि है।
4. कि 'के. नारायणन कुट्टी' एवं 'नारायणन कुट्टी' दोनों एक ही व्यक्ति अर्थात मेरे पिता को संदर्भित करते हैं।
5. कि मैं यह घोषित करता हूँ कि मेरे आधार कार्ड एवं ड्राइविंग लाइसेंस में अंकित नाम 'के. नारायण कुट्टी' ही सही एवं वैध नाम है तथा शैक्षणिक अभिलेखों में हुआ अंतर मामूली एवं अनजाने में हुआ है।
6. कि यह शपथ पत्र मेरे पिता के सही नाम की पुष्टि करने एवं अभिलेखों में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

सत्यापन

मैं सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है।

शपथकर्त्ता

सतत अधिगम और योग्यता–आधारित प्रशिक्षण से सिविल सेवाओं में सुधार की पहल

मिशन कर्मयोगी सरकार की एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य सतत अधिगम और योग्यता–आधारित प्रशिक्षण के माध्यम से सिविल सेवाओं में सुधार करना है। इस पहल के अंतर्गत, साधना सप्ताह नामक क्षमता निर्माण कार्यक्रम 2 से 8 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा। इस सप्ताह का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों के बीच कौशल संवर्धन और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनाने को बढ़ावा देना है।

आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में क्षमता निर्माण आयोग के सदस्य (मानव संसाधन) डॉ. आर. बालासुब्रमण्यम ने आज कहा कि मिशन कर्मयोगी सरकारी अधिकारियों को भविष्य के लिए तैयार करने और देश में क्षमता निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किया 'लीफ'

नई दिल्ली, 30 मार्च।

केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के चार्जिंग इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। भारी उद्योग मंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने सोमवार को 'लीफ' यानी 'लाइट इलेक्ट्रिक–व्हीकल एक्सेलेरेशन फोरम (एलईएएफ)' लॉन्च किया, जो एक इंडस्ट्री–नेतृत्व वाला मंच है।

यह फोरम एक निष्पक्ष प्लेटफॉर्म के रूप में बनाया गया है, जहां लाइट इलेक्ट्रिक वाहन (एलईवी) सेक्टर से जुड़े सभी स्टेकहोल्डर्स, जैसे वाहन निर्माता (ओईएम), चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर, कंपोनेंट निर्माता और टेक्नोलॉजी प्रदाता, एक साथ काम कर सकें। यह फोरम सरकार, रेगुलेटरी संस्थाओं और इंडस्ट्री संगठनों के साथ मिलकर ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को बढ़ावा देगा और देश में इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों को अपनाने में तेजी लाएगा।

मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि यह पहल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विकास को तेज करेगी और बेहतर इंटरऑपरेबिलिटी, भरोसेमंद सिस्टम और विस्तृत चार्जिंग नेटवर्क के जरिए ईवी इकोसिस्टम को मजबूत बनाएगी। उन्होंने कहा कि यह कदम 'आत्मनिर्भर भारत' के विजन के अनुरूप है और इससे सतत (सस्टेनेबल) मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही कार्बन उत्सर्जन को कम करने में भी मदद मिलेगी। कुमारस्वामी ने यह भी कहा कि एक मजबूत और प्रतिस्पर्धी ईवी इकोसिस्टम बनाने के लिए सरकार और उद्योग के बीच बेहतर सहयोग बेहद जरूरी है।

इस पहल का मकसद चार्जिंग नेटवर्क के बीच बेहतर तालमेल (इंटरऑपरेबिलिटी) बनाना, सिस्टम की विश्वसनीयता बढ़ाना और यूजर्स को एक समान अनुभव देना है, साथ ही सार्वजनिक चार्जिंग सुविधाओं का विस्तार करना भी है। इसके तहत 'लाइट इलेक्ट्रिक कंबाइंड चार्जिंग सिस्टम (एलईसीसीएस)' जैसे कदम उठाए जा रहे हैं, जिसे भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने मंजूरी दी है। यह सिस्टम एक यूनिफाइड कनेक्टर के जरिए स्लो और फास्ट दोनों तरह की चार्जिंग को सपोर्ट करेगा।

यह फोरम अब तक ईवी सेक्टर की 20 से ज्यादा कंपनियों को जोड़ चुका है, जिनमें वाहन निर्माता, चार्जिंग ऑपरेटर, सप्लायर्स और सॉटवेयर कंपनियां शामिल हैं। आने वाले समय में इसमें और संगठनों के जुड़ने की उम्मीद है।

भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास 'मरू संग्राम' में दिखाई स्वदेशी हथियार, ड्रोन और टैंक की ताकत

जोधपुर, 30 मार्च।

भारत–पाकिस्तान बॉर्डर पर भारतीय सेना की कोणार्क कॉर्प्स ने राजस्थान के रेगिस्तानी सेक्टर के आगे के इलाकों में रविवार तक युद्ध अभ्यास पूरा किया। यह अभ्यास सुबह से रात तक चला, जिसमें जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल एवीएस राठी ने मौके पर पहुंचकर टैंक, तोप, हेलीकॉप्टर और ड्रोन सिस्टम का निरीक्षण किया। अभ्यास में स्वदेशी हथियारों के साथ सेना की तैयारी और अलग–अलग हालात में काम करने की क्षमता को परखा गया। कोर ने आधुनिक तकनीक और युद्धक क्षमता का प्रदर्शन करते हुए अपनी बैटल रेडी स्थिति दिखाई।

सेना के अनुसार प्रदर्शन के दौरान सेना ने ड्रोन और काउंटर–ड्रोन सिस्टम पर विशेष जोर दिया। निगरानी से लेकर सटीक हमला करने तक, ड्रोन्स की भूमिका को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। साथ ही, दुश्मन के ड्रोन्स को बेअसर करने वाली तकनीक का भी सफल परीक्षण किया गया। रेतीले टीलों के बीच टैंकों और बीएमपी गाडियों ने अपनी गति और निशाने की क्षमता दिखाई। मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री यूनिट्स ने कठिन भूभाग में मूवमेंट और ऑपरेशन को परखा, जिससे अलग–अलग युद्ध परिस्थितियों में काम करने की तैयारी जांची गई।

तोपखाने में बोफोर्स और अन्य आर्टिलरी गन से लक्ष्य पर सटीक मार की क्षमता का परीक्षण किया गया। अटैक हेलीकॉप्टरों ने हवा से जमीन पर हमले का अभ्यास करते हुए तय लक्ष्यों को निशाना बनाया। अभ्यास में ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम पर खास ध्यान दिया गया। ड्रोन से निगरानी और लक्ष्य की पहचान की गई, जबकि काउंटर सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन को निष्क्रिय करने की तकनीक का परीक्षण किया।

स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड और रुद्र को ऊंचाई वाले क्षेत्रों और रेगिस्तान दोनों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें 20 एमएम की गन, रॉकेट और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें लगी होती हैं। ये हेलिकॉप्टर जमीन पर मौजूद लक्ष्यों पर तेज और सटीक हमला कर सकते हैं।

अभ्यास का प्रमुख फोकस स्वदेशी हथियारों पर रहा। स्ट्रेला–10 सहित कई सिस्टम का इस्तेमाल कर सेना ने आत्मनिर्भरता और नई तकनीक को प्रदर्शित किया। इससे भविष्य के ऑपरेशन में इन सिस्टम की उपयोगिता को परखा गया।

केरल, असम और पुडुचेरी के 2.37 लाख दिव्यांग एवं वरिष्ठ मतदाता करेंगे घर से ही मतदान

नई दिल्ली, 30 मार्च।

चुनाव आयोग 85 वर्ष से अधिक आयु और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतपत्रों के जरिए मतदान की सुविधा प्रदान करता है। केरल, असम और पुडुचेरी में अबतक 2.37 लाख पात्र मतदाताओं ने इस सुविधा के लिए आवेदन दिया है। इन राज्यों में 9 अप्रैल को मतदान है।

चुनाव आयोग ने सोमवार को बताया कि केरल में 1.45 लाख, असम में 19 हजार और पुडुचेरी में दो हजार से अधिक वरिष्ठ एवं दिव्यांग मतदाओं ने इस सुविधा के लिए आवेदन किया है। आवेदन करने वालों में 1.67 लाख वरिष्ठ नागरिक (53.5 प्रतिशत) एवं 70 हजार से अधिक दिव्यांग मतदाता (15.22 प्रतिशत) हैं।

इन सभी को आयोग की ओर से जानकारी दी जाएगी की कब मतदान कर्मी राजनीतिक प्रतिनिधियों के साथ उनके घर मतदान के लिए आएंगे। यह प्रक्रिया 5 अप्रैल तक पूरी कर ली जाएगी। आयोग की ओर से पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है। सुविधा के लिए ऐसे मतदाताओं को अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 दिनों के भीतर अपने संबंधित 'रिटर्निंग अधिकारी' के पास आवेदन करना होता है।

इतिहास के पन्नों में 31 मार्च : जब 'बाबासाहब' को मिला भारत रत्न, राष्ट्र ने डॉ. आंबेडकर को किया नमन

नई दिल्ली, 30 मार्च।

साल का हर दिन इतिहास में कई महत्वपूर्ण घटनाओं का साक्षी रहा है और 31 मार्च भी ऐसी ही एक अहम तारीख है। इसी दिन वर्ष 1990 में भारत के संविधान निर्माता बी.आर. आंबेडकर को मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनके राष्ट्र निर्माण और समाज सुधार में दिए गए अमूल्य योगदान के प्रति श्रद्धांजलि के रूप में दिया गया।

'बाबासाहब' के नाम से प्रसिद्ध डॉ आंबेडकर ने भारतीय समाज में व्याप्त जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ जीवनभर संघर्ष किया। वे न केवल एक महान विधिवेत्ता और अर्थशास्त्री थे, बल्कि एक दूरदर्शी सामाजिक सुधारक भी थे, जिन्होंने समाज के वंचित और पिछड़े वर्गों को अधिकार दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत की आजादी के आंदोलन में भी उनकी सक्रिय भागीदारी रही। स्वतंत्रता के बाद उनका योगदान और भी महत्वपूर्ण हो गया, जब उन्हें देश के संविधान निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए एक ऐसे संविधान का निर्माण किया, जो समानता, स्वतंत्रता और न्याय के मूल सिद्धांतों पर आधारित है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1504 – सिखों के गुरु अंगद देव जी का जन्म। वह गुरु नानक देव जी के बाद सिखों के दूसरे गुरू थे।

1727 – दुनिया के महान भौतिकशास्त्रियों में शुमार आइजक न्यूटन का 84 वर्ष की आयु में लंदन में निधन।

1774 – भारत में डाक सेवा शुरू, पहला डाकघर खुला।

1870 – अमेरिका में पहली बार किसी अश्वेत नागरिक ने वोट दिया। अश्वेतों को समान अधिकार दिलाने की दिशा में यह एक बड़ी कामयाबी थी।

1889 – पेरिस का मशहूर एफेल टावर आधिकारिक तौर पर खुला।

1959 – 14वें दलाई लामा, तेनज़िन ग्यातसो, भारत की सीमा पार करी और राजनीतिक शरण ली।

1980 – अमेरिका के महान फर्राटा धावक जेसी ओवंस का निधन। ओवंस ने 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में अपने देश के लिए चार स्वर्ण पदक जीते थे।

1981 – एक घरेलू विमान का अपहरण करने वाले इंडोनेशिया के पांच आतंकवादियों में से चार को थाइलैंड के बैंकाक में मार गिराया गया। विमान में सवार सभी 55 लोग सुरक्षित।

1983 – कोलम्बिया में भूकंप से लगभग 5000 लोगों की मौत।

1989 – पैरिस की पहचान माने जाने वाले विशाल एफिल टावर को आधिकारिक तौर पर खोला गया। फ्रांस की क्रांति की शताब्दी के मौके पर बनी 300 मीटर ऊंची लोहे की इस इमारत को गुस्ताव एफिल की प्राद्यौगिक कुशलता का बेमिसाल नमूना माना जाता है।

1998 – भारत और चीन इंटर गवर्नमेंटल कांरेस आन कल्चरल पॉलिसीज के लिए गठित यूनेस्को की मसौदा समिति के सदस्य निर्वाचित।

2000 – 22 वर्ष बाद जापान के उत्तरी धोकाइडु द्वीप में दाते के निकट उसू ज्वालामुखी फिर सक्रिय।

2004 – अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक नाइट क्लब में आग लगने से 175 लोगों की मौत।

2007 – विश्व तैराकी चैम्पियनशिप में माइकल फ़ेल्प्स ने छह स्वर्ण हासिल किये।

सऊदी अरब की गुफा में मिला 1800 साल पुराना चीतों का ममी, वैज्ञानिक दंग रह गए?

नई दिल्ली, 30 मार्च।

वैज्ञानिकों ने सऊदी अरब के उत्तरी हिस्से में स्थित अरार शहर के पास बने प्राचीन गुफाओं से चीतों की ममी बरामद हुई है. ममी का मतलब यहां उन मृत शरीरों से है, जिन्हें नैचुरल तरीके से केमिकल और जगह के हिसाब से संरक्षित किया जाता था. हालांकि इन चीतों के अवशेष प्राकृतिक रूप से संरक्षित मिले हैं. यह खोज ना केवल अरब प्रायद्वीप में चीतों की प्राचीन मौजूदगी का दुर्लभ प्रमाण देती है, बल्कि उनके जेनेटिक इतिहास को समझने में भी अहम मानी जा रही है. शोधकर्ताओं के मुताबिक, इन अवशेषों की उम्र 130 साल से लेकर 1800 साल से अधिक तक के बीच में है.

खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को सात चीतों के ममी मिले, जबकि 54 अन्य चीतों की हड्डियाँ भी बरामद की गईं. यह खोज चीतों के ऐतिहासिक विस्तार और उनके व्यवहार को समझने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं. इटली की यूनिवर्सिटी ऑफ लोरेंस से जुड़ीं वैज्ञानिक जोआन मादुरेल–मलापेइरा ने समाचार एजेंसी एपी से कहा, "यह ऐसा कुछ है, जो मैंने पहले कभी नहीं देखा." हालांकि वह इस शोध का हिस्सा नहीं रहीं.

वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार, इन चीतों की आंखें धुंधली, अंग सिकुड़े हुए और शरीर सूखे खोल जैसे दिखाई देते हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इन चीतों का प्राकृतिक रूप से ममी बनना, गुफाओं के बेहद शुष्क वातावरण और स्थिर तापमान के कारण हुआ. यह शोध जर्नल Communications Earth and Environment में प्रकाशित हुआ है.

हालांकि, वैज्ञानिक अब भी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं कर पाए हैं कि इतने बड़े पैमाने पर चीतों का ममीकरण कैसे हुआ या इतनी संख्या में चीते इन गुफाओं में क्यों मौजूद थे? एक संभावना यह जताई जा रही है कि ये गुफाएँ मादा चीतों और उनके शावकों के लिए सुरक्षित ठिकाने (डेनिंग साइट) के रूप में इस्तेमाल होती हों.

इतने बड़े जानवरों का इस तरह सुरक्षित मिलना बेहद असामान्य है. इसके लिए ना केवल अनुकूल पर्यावरणीय परिस्थितियाँ जरूरी होती हैं, बल्कि शवों को शिकारी जानवरों से बचाव भी मिलना चाहिए. इससे पहले ऐसी ही एक दुर्लभ खोज रूस में मिले सेबर–टूथ्ड कैट के शावक की ममी के रूप में सामने आई थी. शोध से जुड़े अहमद बुग ने मीडिया रिपोर्ट में कहा,"दुनिया के इस हिस्से में इतने पुराने चीतों के सुरक्षित प्रमाण मिलना पूरी तरह से अभूतपूर्व है."

एक समय था जब चीते, अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों और एशिया के कुछ क्षेत्रों में पाए जाते थे लेकिन आज वे अपने मूल क्षेत्र के केवल 9 प्रतिशत हिस्से तक ही सीमित रह गए हैं. आवास के नुकसान, बिना नियंत्रण के शिकार और शिकार प्रजातियों की कमी के कारण अरब प्रायद्वीप में दशकों से चीते नहीं देखे गए हैं

कृषि अवशेष से बनेंगी सड़कें, सीएसआईआर ने बायो–बिटुमेन तकनीक का किया हस्तांतरण

नई दिल्ली, 30 मार्च।

बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) ने सोमवार को अपनी अभिनव तकनीक "लिग्नोसेलुलोसिक बायोमास से बायो–बिटुमेन खेतों के अवशेष से सड़कों तक" के बड़े पैमाने पर औद्योगिक उपयोग के लिए तकनीक का हस्तांतरण किया।

सीएसआईआर में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, पृथ्वी विज्ञान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेन्द्र सिंह, सीएसआईआर की महानिदेशक एन. कलाईसेल्वी तथा विभिन्न मंत्रालयों, सीएसआईआर संस्थानों, उद्योग और नीति–निर्माताओं के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

श्री शिवराज सिंह चौहान ने बायो–बिटुमेन तकनीक को ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी कदम बताते हुए कहा कि यह तकनीक कृषि को बुनियादी ढांचे और नवाचार को जोड़ता है। यह तकनीक भारत के जलवायु लक्ष्यों, नेट ज़ीरो प्रतिबद्धताओं, आत्मनिर्भर भारत, राष्ट्रीय बायो–ऊर्जा मिशन और सर्कुलर इकोनॉमी जैसी पहलों के अनुरूप है। इसके उपयोग से किसानों को अतिरिक्त आय के अवसर मिलेंगे और पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी।

डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि यह पहल भारत की आत्मनिर्भरता, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण और "वेस्ट टू वेल्थ"

की सोच को दर्शाती है। यह तकनीक कृषि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों के बीच प्रभावी समन्वय का उदाहरण है, जिसमें सार्वजनिक–निजी भागीदारी का महत्वपूर्ण योगदान है।

इस अवसर पर सीएसआईआर की महानिदेशक एन कलाइसेल्वी ने कहा कि यह विकास पेट्रोलियम–आधारित सामग्री से जैव–आधारित सामग्री की ओर एक बड़ा बदलाव है और यह संस्थान देश के विकास के लिए नई तकनीकों को आगे बढ़ाता रहेगा।

यह तकनीक सीएसआईआर–केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान और सीएसआईआर–भारतीय पेट्रोलियम संस्थान द्वारा विकसित की गई है। इसमें कृषि अवशेषों और बायोमास को थर्मो–केमिकल प्रक्रिया से परिवर्तित कर पर्यावरण–अनुकूल बायो–बिटुमेन बनाया जाता है। यह नवाचार पारंपरिक पेट्रोलियम–आधारित बिटुमेन का एक नवीकरणीय और कम–कार्बन विकल्प प्रदान करता है।

भारत में प्रोडक्ट डिजाइन नहीं करने वाली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को नहीं मिलेगा सरकारी फायदाः केन्द्रीय मंत्री

नई दिल्ली, 30 मार्च।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को साफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) में शामिल कंपनियों को सरकारी सहायता तभी मिलेगी, जब वे भारत में प्रोडक्ट डिजाइन पर गंभीरता से निवेश करेंगी। राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रोत्साहन और समर्थन अब इस बात से जुड़े होंगे कि कंपनियां देश में डिजाइन, क्वालिटी और इंजीनियरिंग क्षमताओं को कितना विकसित कर रही हैं। मंत्री ने चेतावनी दी कि अगर कंपनियां सरकार की चार प्रमुख मांगों पर काम नहीं करती हैं, तो वह अगली इंडस्ट्री मीटिंग में शामिल भी नहीं होंगी।

श्री वैष्णव ने कहा कि कंपनियों द्वारा डिजाइन और क्वालिटी क्षमताओं को विकसित करने की गति से वे निराश हैं, और अगर सुधार नहीं हुआ तो सरकार कड़े फैसले लेने को तैयार है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, "अगर इंडस्ट्री हमारी अपेक्षाओं के मुताबिक कदम नहीं उठाती है, तो हम आगे की मंजूरी और फंडिंग रोक सकते हैं।"

सरकार की अपेक्षाओं को बताते हुए मंत्री ने कहा कि कंपनियों को केवल असेंबली या बेसिक मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें कॉन्सेप्चुअल डिजाइन, इंजीनियरिंग डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग डिजाइन तक अपनी क्षमता बढ़ानी होगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि जिन प्रोजेक्ट्स को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है, उनमें भी अगर शर्तें पूरी नहीं हुईं, तो फंड जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, "जिन आवेदनों को मंजूरी दी जा चुकी है,

उनमें भी हम पैसा नहीं देंगे अगर हमारी शर्तें पूरी नहीं हुईं।" गौरतलब हो, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने इस स्कीम के चौथे चरण में 29 आवेदनों को मंजूरी दी है, जिनमें कुल 7,104 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। ईसीएमएस के तहत कुल 59,350 करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य था, जबकि अब तक 61,671 करोड़ रुपए के प्रस्तावों को मंजूरी दी जा चुकी है।

श्री वैष्णव ने कहा कि असली वैल्यू तभी बनती है, जब डिजाइन भारत में किया जाता है। उन्होंने बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, लेकिन डिजाइन का महत्व उससे ज्यादा है क्योंकि यह ज्यादा जटिल और रणनीतिक प्रक्रिया है। वैश्विक गुणवत्ता मानकों की आवश्यकता पर जोर देते हुए, उन्होंने कहा कि ग्लोबल स्तर की क्वालिटी के लिए सिक्स सिग्मा जैसी प्रक्रियाएं जरूरी हैं। उन्होंने कहा, "यह होना ही चाहिए; इसके बिना प्रोडक्ट पूरा नहीं माना जाएगा।" उन्होंने विश्वसनीयता, सटीकता और निरंतरता पर सरकार के फोकस को रेखांकित किया।

बैंक सख्त कानूनी ढांचे में ग्राहकों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं: वित्त मंत्री

नई दिल्ली, 30 मार्च।

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा है कि देश के बैंक, ग्राहकों के डाटा की सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त कानूनी और नियामक ढांचे के तहत काम करते हैं। वित्तमंत्री ने आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में यह जानकारी दी।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि रिजर्व बैंक द्वारा जारी 'अपने ग्राहक को जानें'–केवाईसी ढांचे और दिशा–निर्देशों के अंतर्गत बैंकों को ग्राहक जानकारी की गोपनीयता बनाए रखनी होती है।

उन्होंने बताया कि पांच अलग–अलग अधिनियम हैं और बैंकों को इन कानूनों का पालन करना होता है। इनमें भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, क्रेडिट सूचना और कंपनी अधिनियम तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थान अधिनियम शामिल हैं।

श्रीमती सीतारमण ने कहा कि डाटा केवल आवश्यकता के आधार पर एकत्र किया जाता है और जरूरत के अनुसार अधिकारियों के साथ साझा किया जाता है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि धोखाधड़ी या अनधिकृत डाटा साझाकरण के मामलों में, रिजर्व बैंक या संबंधित अधिकारियों से शिकायत की जा सकती है। अधिकारी ऐसी शिकायतों पर आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

फिर जाएंगे चंद्रमा के पास... आर्टेमिस II मिशन के चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह तैयार, प्रक्षेपण एक अप्रैल को

वाशिंगटन, 30 मार्च।

अमेरिका के राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रशासन (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के पहले मानवयुक्त मिशन 'आर्टेमिस II' के चारों अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह तैयार हैं। इस मिशन का प्रक्षेपण एक अप्रैल को होना है। चारों अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन ने कहा कि हमें इस पल का इंतजार हैं। हम इस ऐतिहासिक प्रक्षेपण के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

सीबीएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, नासा (नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन) के अनुसार, आधिकारिक तौर पर 49 घंटे और 40 मिनट की उलटी गिनती 31 मार्च को भारतीय समयानुसार देर रात (4:44 बजे पूर्वी समयानुसार) शुरू होने वाली है। यदि सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो रॉकेट 1 अप्रैल को शाम 6:24 बजे (पूर्वी डेलाइट समय) फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरेगा। कमांडर वाइसमैन ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उनकी टीम और रॉकेट दोनों पूरी तरह से तैयार हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी स्थिति (जैसे कि तकनीकी कारणों से प्रक्षेपण टलना) के लिए मानसिक रूप से 100 प्रतिशत तैयार हैं।

आर्टेमिस II मिशन का उद्देश्य 50 से अधिक वर्ष के बाद मनुष्य को फिर से चंद्रमा के करीब ले जाना है। यह मिशन 1972 के अपोलो 17 के बाद चंद्रमा की ओर जाने वाला पहला मानव मिशन है। यह चंद्रमा के चारों ओर एक लाईबाई (परिक्रमा) करेगा। यह चंद्रमा की सतह पर नहीं उतरेगा, बल्कि भविष्य के आर्टेमिस III के लिए प्रणालियों

का परीक्षण करेगा। यह लगभग 10 दिन की यात्रा होगी। चालक दल ओरियन कैप्सूल (अंतरिक्ष यान) में यात्रा करेगा। यह मिशन नासा को अंतरिक्ष यात्रियों के साथ ओरियन के जीवन–सहायक प्रणालियों के परीक्षण करने की अनुमति देगा।

चारों अंतरिक्ष यात्री कमांडर रीड वाइसमैन, पायलट विक्टर ग्लोवर, मिशन विशेषज्ञ क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसन शुक्रवार को ह्यूस्टन से केनेडी स्पेस सेंटर पहुंच चुके हैं। मेडिकल क्वारंटाइन में रहते हुए उन्होंने रविवार को एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए। वाइसमैन 2019–20 में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 328 दिनों के अभियान के दौरान छह बार स्पेस वॉक कर चुके हैं। वाइसमैन ने कहा, यह पहली बार है जब हम इंसानों को अपने साथ ले जा रहे हैं। यह सब सपने जैसा लगता है। मुझे आराम महसूस हो रहा है। यहां होना अच्छा लग रहा है। उधर, मौसम विज्ञानियों का कहना है कि मौसम के ठीक रहने की 80 प्रतिशत संभावना है।

देशभर में शुरू होने जा रही जनगणना, डिजिटल प्रक्रिया से लेकर जाति गणना तक! जानिए क्या है नया

नई दिल्ली, 30 मार्च।

भारत में जनगणना सिर्फ एक आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि देश की दिशा तय करने वाली सबसे अहम प्रशासनिक प्रक्रिया है. हर 10 साल में होने वाली यह कवायद सरकार को यह समझने में मदद करती है कि देश की आबादी, संसाधन और जरूरतें किस दिशा में बढ़ रही हैं. अब जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं, और इस बार यह प्रक्रिया पहले से कहीं ज्यादा आधुनिक और तकनीक आधारित होने वाली है. डिजिटल सिस्टम, नए सवाल और अपडेटेड डेटा कलेक्शन के जरिए सरकार नीतियों को और ज्यादा सटीक बनाने की तैयारी में है जिससे आम जनता को सीधा फायदा मिल सके.

भारत में जनगणना कराने की जिम्मेदारी पूरी तरह केंद्र सरकार की होती है. संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत इसे संघ सूची में रखा गया है, यानी इस पर सिर्फ केंद्र ही फैसला ले सकता है. संघ सूची में जनगणना को क्रमांक 69 पर रखा गया है, जिससे इसकी देशभर में अहमियत साफ दिखती है. इसके अलावा, जनगणना का पूरा काम कुछ तय कानूनों के अनुसार होता है.

जनगणना अधिनियम 1948 और जनगणना नियम 1990 यह तय करते हैं कि डेटा कैसे इकट्ठा होगा, लोगों से क्या जानकारी ली जाएगी और पूरी प्रक्रिया कैसे सही तरीके से पूरी की जाएगी. यानी जनगणना कोई साधारण सर्वे नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से कानून के तहत चलने वाली व्यवस्थित प्रक्रिया है.

भारत में पिछली जनगणना साल 2011 में हुई थी, और अब अगली जनगणना 2027 में होने वाली है. यह देश की 16वीं जनगणना होगी और आजादी के बाद की 8वीं जनगणना मानी जाएगी. सरकार ने इसके लिए एक तय समय भी रखा है 1 मार्च 2027 की आधी रात को आधार समय (रेफरेंस डेट) माना जाएगा, यानी उसी समय के हिसाब से पूरे देश की आबादी का आंकड़ा तय होगा. इसकी तैयारी काफी पहले से शुरू हो चुकी है. 16 जून 2025 को पहली अधिसूचना जारी की गई थी, जिससे प्रक्रिया की शुरुआत हुई.

इसके बाद 7 जनवरी 2026 को पहले चरण की अधिसूचना आई, जिसमें 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2026 तक का समय

तय किया गया है. इस दौरान घर–घर जाकर शुरुआती जानकारी जुटाई जाएगी. यानि साफ है कि जनगणना एक दिन का काम नहीं, बल्कि कई चरणों में धीरे–धीरे पूरा होने वाली बड़ी प्रक्रिया है.

जनगणना को दो चरणों में पूरा किया जाएगा. पहले चरण में घर–घर जाकर परिवार से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी. इस दौरान राज्यों को 30 दिनों की अवधि तय करने की छूट दी गई है. दूसरे चरण में जनसंख्या से जुड़े विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे. इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि जनगणना में जाति से संबंधित जानकारी भी शामिल की जाएगी.

जनगणना 2027 की सबसे बड़ी खासियत है डिजिटल प्रक्रिया और सेल्फ एन्यूमरेशन. अब नागरिक खुद ऑनलाइन माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे. यह सुविधा घर–घर गणना शुरू होने से पहले 15 दिनों के लिए उपलब्ध होगी. जनगणना 2027 न केवल आंकड़ों का संग्रह है, बल्कि यह देश के विकास की दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण कदम है. नई डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी प्रक्रिया के साथ यह जनगणना पहले से ज्यादा प्रभावी और आधुनिक बनने जा रही है.

जनगणना अधिनियम की धारा 15 के तहत नागरिकों द्वारा दी गई जानकारी पूरी तरह गोपनीय रखी जाती है. इन आंकड़ों को न तो RTI के तहत साझा किया जा सकता है और न ही किसी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सकता है. केवल समेकित आंकड़ों का ही उपयोग किया जाता है, जिससे व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रहती है.

ज्ञान भारतम मिशन के तहत एशियाटिक सोसायटी ने स्कैन कीं 2,033 पांडुलिपियां

नई दिल्ली, 30 मार्च।

लोकसभा में सोमवार को जानकारी दी गई कि एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता ने 23 मार्च तक कुल 2,033 पांडुलिपियों को स्कैन किया है। इन पांडुलिपियों में कुल 1,46,099 पेज शामिल हैं। यह कार्य ज्ञान भारतम मिशन के तहत संस्था को क्लस्टर सेंटर बनाए जाने के बाद किया गया।

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लिखित जवाब में बताया कि एशियाटिक सोसायटी अब तक 11,528 पांडुलिपियों को डिजिटाइज कर चुकी है, जिनमें कुल 5,72,890 पेज शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इस पहल से देश की प्राचीन ज्ञान परंपरा को संरक्षित करने में मदद मिल रही है।

मंत्री ने बताया कि संस्था में आग से बचाव और आपदा प्रबंधन के लिए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। सोसायटी का संपर्क राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, पश्चिम बंगाल सरकार के फायर एवं इमरजेंसी विभाग और स्थानीय पुलिस से लगातार बना रहता है।

उन्होंने बताया कि सोसायटी की ऐतिहासिक इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधीन है और इसके संरक्षण व मरम्मत का काम एएसआई द्वारा किया जाता है।

शेखावत ने कहा कि म्यूजियम में रखी पांडुलिपियों, दुर्लभ पुस्तकों और वस्तुओं के लिए उचित तापमान और नमी बनाए रखने की व्यवस्था की गई है। संस्था समय–समय पर इनकी स्थिति की जांच भी करती है, जो क्यूरेटर की निगरानी में कैटलॉगिंग स्टाफ द्वारा की जाती है।

उन्होंने बताया कि सोसायटी के पास अपना संरक्षण और बाइंडिंग सेक्शन भी है। वर्ष 2022 में पांडुलिपि संरक्षण केंद्र बनने के बाद से अब तक 35,624 पन्नों का संरक्षण और 4,596 दुर्लभ पन्नों की मरम्मत की जा चुकी है। म्यूजियम और आर्काइव सेक्शन में कैटलॉग तैयार करना एक नियमित प्रक्रिया के रूप में जारी है।

94 हजार टन एलपीजी के साथ स्वदेश लौट रहे हैं दो और भारतीय एलपीजी टैंकर

नई दिल्ली, 30 मार्च। दो और भारतीय एलपीजी टैंकर, 94 हजार टन एलपीजी के साथ स्वदेश लौट रहे हैं। दोनों टैंकरों ने युद्धग्रस्त होर्मुज जल–डमरू–मध्य को सुरक्षित पार कर लिया है। एक एलपीजी टैंकर बीडब्ल्यू टीवाईआर कल मुंबई पहुंच सकता है, वही दूसरे टैंकर बीडब्ल्यू ईएलएम के पहली अप्रैल को न्यू मैंगलोर पहुंचने की उम्मीद है। अमरीका और इस्राएल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों और तेहरान की व्यापक जवाबी कार्रवाई के कारण होर्मुज जल–डमरू–मध्य से जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो गई थी। यह संकरा जलमार्ग खाड़ी देशों से दुनिया भर में तेल और गैस के निर्यात का प्रमुख मार्ग है। हालांकि, ईरान ने पिछले सप्ताह कहा था कि "गैर–शत्रुतापूर्ण जहाज" इस जलमार्ग से गुजर सकते हैं।

इससे पहले, भारत के चार एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से जल–डमरू–मध्य से गुजर चुके हैं। पाइन गैस और जग वसंत नामक जहाज, जिनमें 92 हजार 612 टन एलपीजी थी, 26 से 28 मार्च के बीच भारतीय बंदरगाहों पर पहुंच थे।

घर से निकलते वक्त फोन का वाई–फाई जरूर बंद करें, जानें आखिर क्यों

नई दिल्ली, 30 मार्च।

ज़्यादातर लोगों की आदत होती है कि वे अपने फोन का वाई–फाई हर समय ऑन रखते हैं. लेकिन साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह उतना अच्छा नहीं है. घर से निकलते समय आप में से कई लोग जो एक चीज भूल जाते हैं, वह है फोन का वाई–फाई बंद करना. इसे यह सोचकर हल्के में न लें कि वाई–फाई बंद नहीं करने से क्या दिक्कत होगी. जब फोन का वाई–फाई बंद नहीं होता, तो डिवाइस चुपचाप सिग्नल भेजता रहता है. यह सिर्फ कनेक्ट करने के लिए किसी नेटवर्क को खोजने का सिग्नल नहीं होता, बल्कि यह दूसरों को यह भी जानकारी देता है कि आप कौन हैं और कहां हैं. इतना ही नहीं, याद रखें कि ऐसा करके आप हैकर्स को अपने फोन में घुसने का रास्ता भी दे रहे हैं.

आइए, फोन पर वाई–फाई के इस्तेमाल के बारे में साइबर सुरक्षा रिसर्चर्स की कुछ चेतावनियों को विस्तार से जानते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर आप वाई–फाई बंद किए बिना फोन लेकर घर से बाहर जाते हैं, तो आपके फोन के पास एक हिडन एक्सपोजर विंडो बन जाती है. कनेक्ट न होने पर भी, फोन पहले से कनेक्टेड वाई–फाई नेटवर्क को खोजने की कोशिश में रिक्वेस्ट भेजता रहता है. रिसर्च में पाया गया है कि हैकर्स के लिए उन सिग्नल्स को पकड़ने के लिए इतना ही काफी है. जब स्मार्टफोन का वाई–फाई बंद नहीं होता, तो बैकग्राउंड में चल रही ऐसी गतिविधियों के बारे में फोन यूजर्स को पता भी नहीं चलता. कहा जाता है कि यह स्थिति, जो आपके फोन की सुरक्षा

को भी खतरे में डालती है, आपके होम नेटवर्क से थोड़ी दूर जाते ही हो सकती है. इसलिए, घर से निकलते समय फोन का वाई–फाई बंद रखना ही बेहतर है.

जब आप फोन पर वाई–फाई बंद नहीं करते, तो दूसरे लोग आपका नाम और लोकेशन भी जान सकते हैं. इसमें एक और खतरा छिपा है कि फोन गलती से किसी नकली नेटवर्क से वाई–फाई के जरिए कनेक्ट हो सकता है. यात्रा के दौरान और भीड़–भाड़ वाली सार्वजनिक जगहों पर, ऐसे अनजान नेटवर्क से वाई–फाई के जरिए कनेक्ट होने से आपका फोन हैक भी हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि सभी वाई–फाई नेटवर्क पासवर्ड से सुरक्षित हों. अनजान वाई–फाई नेटवर्क से फोन को जोड़ने पर आपकी ब्राउज़िंग जानकारी, बिना एन्क्रिप्ट की गई जानकारी और लॉगिन एड्रेस लीक हो सकते हैं. इसी वजह से कहा जाता है कि मोबाइल फोन और लैपटॉप जैसे पर्सनल/प्राइवेट डिवाइस को पब्लिक वाई–फाई नेटवर्क से जोड़ते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए.